दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 2-06-2026

विषय सूची

मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक संरक्षण कवच के रूप में अरावली पर्वतमाला

भारत में सूक्ष्म वित्त का पुनःपरिकल्पन

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में डिजिटल संप्रभुता

संक्षिप्त समाचार

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर

पीएम स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण

शांग्री-ला संवाद

बन्नी घासभूमि

मरुस्थलीकरण के विरुद्ध प्राकृतिक संरक्षण कवच के रूप में अरावली पर्वतमाला

संदर्भ

- हाल ही में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आए धूल-आंधियों ने उत्तरी भारत को धूल-आंधियों से सुरक्षित रखने में अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका को उजागर किया।

उत्तर-पश्चिमी भारत में धूल-आंधियाँ

- धूल-आंधियाँ उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रायः मानसून-पूर्व अवधि, अर्थात् अप्रैल से जून के महीनों के दौरान आती हैं।
- भूमि सतह के तीव्र ताप से शुष्क एवं अस्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो धूल-आंधियों के निर्माण के लिए अनुकूल होती हैं।
  - प्रबल दक्षिण-पश्चिमी एवं पश्चिमी पवनें थार मरुस्थल तथा उससे सटे क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में धूल को उत्तरी भारत की ओर ले जाती हैं।

अरावली पर्वतमाला उत्तरी भारत की रक्षा कैसे करती है?

- लगभग 692 किलोमीटर (430 मील) लंबाई में उत्तर-पूर्वी दिशा में विस्तृत अरावली पर्वतमाला, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से होकर दिल्ली तक पहुँचती है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है।
  - इस पर्वतमाला का लगभग दो-तिहाई भाग राजस्थान में स्थित है।
- अरावली जल-पुनर्भरण तंत्रों को समर्थन प्रदान करती है तथा साबरमती और लूनी जैसी नदियों का उद्गम स्थल है।
- यह क्षेत्र बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, ताँबा, स्वर्ण तथा टंग्स्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है।
- **महत्त्व:** अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल और सघन जनसंख्या वाले इंडो-गंगा के मैदानों के मध्य एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है।
- धूल से युक्त पवनें जब अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं, तो उनकी गति कम हो जाती है, जिससे रेत एवं धूल के कण पश्चिमी ढलानों पर ही जम जाते हैं।
- वनों एवं वनस्पतियों की उपस्थिति वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों को अवरुद्ध कर उनकी आवाजाही को कम करती है।
- यह पर्वतमाला मरुस्थलीय परिस्थितियों के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने में सहायक है तथा कृषि एवं शहरी क्षेत्रों को अत्यधिक धूल जमाव से सुरक्षित रखती है।

अरावली पर्वतमाला के क्षरण के कारण

- ग्रेनाइट, लाल सिलिका, संगमरमर तथा अन्य खनिजों के व्यापक खनन ने पर्वतमाला की पहाड़ियों एवं प्राकृतिक भू-दृश्यों को क्षति पहुँचाई है।
- वनों एवं प्राकृतिक वनस्पति के हटने से धूल को अवरुद्ध करने तथा मृदा को स्थिर बनाए रखने की अरावली की क्षमता में कमी आई है।
- वन एवं चारागाह भूमि का बस्तियों तथा कृषि क्षेत्रों में रूपांतरण पारिस्थितिकीय सहनशीलता को कमजोर कर रहा है।

अरावली ग्रीन वॉल पहल

- वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली 'ग्रीन वॉल' परियोजना का शुभारंभ किया।
- इस पहल का उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के चारों ओर पाँच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार करना है।
- यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों को आच्छादित करती है।
- इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अवनत भूमि का पुनर्स्थापन करना तथा मरुस्थलीकरण के विरुद्ध पारिस्थितिकीय सहनशीलता को सुदृढ़ बनाना है।

स्रोत: IE

भारत में सूक्ष्म वित्त का पुनःपरिकल्पन

संदर्भ

- हाल ही में अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि यद्यपि सूक्ष्म वित्त ने भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है, भविष्य की वृद्धि को बनाए रखने के लिए मध्यम वित्त (मेसो-फाइनेंस) और बढ़ते उद्यमों के लिए सशक्त वित्तीय सेवाओं की ओर परिवर्तन आवश्यक होगा।

सूक्ष्म वित्त क्या है?

- सूक्ष्म वित्त का आशय छोटे पैमाने की वित्तीय सेवाओं, विशेषकर ऋण, से है जो निम्न-आय वाले परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें औपचारिक बैंकिंग संस्थानों तक पहुँच नहीं होती।
- इस अवधारणा को वैश्विक पहचान 1976 में बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक के माध्यम से मिली, जिसने बिना संपार्श्विक (कोलेटरल) के गरीब परिवारों को समूह-आधारित ऋण को लोकप्रिय बनाया।

पारंपरिक सूक्ष्म वित्त मॉडल की सफलता

- भारत का सूक्ष्म वित्त क्षेत्र मुख्यतः संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल पर आधारित है। इसने लाखों निम्न-आय वाले परिवारों, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं, को औपचारिक ऋण तक पहुँच प्रदान की है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लागू स्व-सहायता समूह-बैंक लिंक कार्यक्रम ने 144 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 17 करोड़ से अधिक परिवारों को सशक्त बनाया है।
- लगभग 46% सूक्ष्म वित्त ऋण उन परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी मासिक आय ₹20,000 से कम है, जिससे आय-सृजन गतिविधियों और परिसंपत्ति निर्माण को समर्थन मिलता है।

सूक्ष्म वित्त से संबंधित सरकारी पहलें

- **क्रेडिट सूचना साझा करने का आदेश**: आरबीआई ने सभी सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को CRIF हाई मार्क और CIBIL जैसे क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है, जिससे उधारकर्ताओं का क्रेडिट इतिहास उचित मूल्यांकन हेतु उपलब्ध हो सके।
- **सूक्ष्म वित्त ऋण हेतु आरबीआई का संशोधित नियामक ढाँचा, 2022**: सभी विनियमित संस्थाओं (बैंक, एनबीएफसी, एनबीएफसी-एमएफआई, एसएफबी) के लिए एक समान नियामक ढाँचा प्रदान करता है ताकि उधारकर्ता संरक्षण और जिम्मेदार ऋण को बढ़ावा मिल सके।
- **SHG-बैंक लिंक कार्यक्रम**: स्व-सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ता है और आय-सृजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना**: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ₹20 लाख तक का बिना संपार्श्विक ऋण प्रदान करती है।
- **नाबार्ड पुनर्वित्त समर्थन**: सूक्ष्म वित्त संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है ताकि वंचित वर्गों तक ऋण प्रवाह बढ़ाया जा सके।

सूक्ष्म वित्त मॉडल की सीमाएँ

- पारंपरिक सूक्ष्म वित्त मॉडल मुख्यतः छोटे पैमाने की आजीविका गतिविधियों और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।
- उच्च ब्याज दरें इसे उन उद्यमों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं जिन्हें बड़े निवेश और लंबी पुनर्भुगतान अवधि की आवश्यकता होती है।
- मानकीकृत ऋण उत्पाद प्रायः उधारकर्ताओं की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।
- पर्याप्त बचत और बीमा के बिना अत्यधिक ऋण पर निर्भरता वित्तीय असुरक्षा बढ़ाती है।
- विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थानों से कई बार ऋण लेने से ऋण-जाल का जोखिम बढ़ा है, जहाँ क्षेत्र की लगभग 8–10% परिसंपत्तियाँ उन उधारकर्ताओं से जुड़ी हैं जिनके पास चार से अधिक ऋणदाता हैं।

मेसो-फाइनेंस क्या है?

- मेसो-फाइनेंस उन वित्तीय सेवाओं को संदर्भित करता है जो सूक्ष्म वित्त और पारंपरिक बैंक ऋण के बीच के अंतर को समाप्त करते हैं।
- यह सूक्ष्म वित्त ऋणों से बड़ा और अधिक लचीला वित्त प्रदान करता है, लेकिन पारंपरिक वाणिज्यिक बैंक ऋणों से छोटा अवं कम औपचारिक होता है।
- यह व्यवसाय विस्तार, परिसंपत्ति निर्माण, रोजगार सृजन और ग्रामीण आर्थिक विकास को समर्थन देता है।

सूक्ष्म वित्त और मध्यम वित्त में अंतर

पहलू	सूक्ष्म वित्त	मेसो-फाइनेंस
ऋण आकार	छोटे ऋण	मध्यम आकार के ऋण
उद्देश्य	कार्यशील पूंजी और आजीविका गतिविधियाँ	व्यवसाय विस्तार और परिसंपत्ति निर्माण

पुनर्भुगतान अवधि	अल्पकालिक	मध्यम से दीर्घकालिक
लक्षित समूह	निम्न-आय वाले परिवार और सूक्ष्म उद्यम	उदीयमान सूक्ष्म और लघु उद्यम
उदाहरण	सिलाई मशीन या दुग्ध पशु खरीदना	डेयरी फार्म, खाद्य प्रसंस्करण इकाई या ग्रामीण उद्यम स्थापित करना

मध्यम वित्त की ओर संक्रमण में चुनौतियाँ

- **उच्च ऋण जोखिम**: बड़े ऋण आकार से चूक और वित्तीय हानि का जोखिम बढ़ता है।
- **कमजोर ऋण मूल्यांकन प्रणाली**: वित्तीय संस्थानों को अधिक सशक्त उधारकर्ता मूल्यांकन और नकदी प्रवाह आकलन तंत्र की आवश्यकता है।
- **व्यवसाय समर्थन सेवाओं की आवश्यकता**: बढ़ते उद्यमों को वित्त के साथ-साथ सतत निगरानी, मार्गदर्शन और बाज़ार संपर्क की आवश्यकता होती है।
- **नियामक बाधाएँ**: वर्तमान नियामक ढाँचे और वित्तीय संस्थान मुख्यतः या तो सूक्ष्म वित्त या पारंपरिक बैंकिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

मध्यम वित्त के सफल मॉडल

- **थाईलैंड का कृषि और कृषि सहकारी बैंक**: किसान समूहों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्यमों को मध्यम आकार के ऋण प्रदान करता है, जिससे वे निर्वाह गतिविधियों से आगे बढ़ सकें।
- **बांग्लादेश में BRAC**: छोटे उद्यम ऋण शुरू किए, जो उन व्यवसायों का समर्थन करते हैं जो पारंपरिक सूक्ष्म वित्त से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन वाणिज्यिक बैंक ऋण तक पहुँचने के लिए बहुत छोटे हैं।
- **KfW विकास बैंक**: अफ्रीका और एशिया में SME-वित्तपोषण कार्यक्रमों का समर्थन करता है जो बढ़ते उद्यमों को मध्यम पैमाने का ऋण प्रदान करते हैं।
- **भारत में**: मान देशी महिला सहकारी बैंक और कई छोटे वित्त बैंक सफल सूक्ष्म वित्त ग्राहकों को बड़े उद्यम ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे मध्यम वित्त दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं।

आगे की राह

- वित्तीय सहायता के साथ क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और व्यवसाय विकास सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
- छोटे वित्त बैंक, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को उद्यम विस्तार हेतु अनुकूलित वित्तीय उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- वित्तीय संस्थानों को ऋण के साथ बचत, बीमा और पेंशन उत्पाद भी प्रदान करने चाहिए ताकि परिवारों की लचीलापन बढ़े।
- ऋण मूल्यांकन को मानकीकृत मॉडलों के बजाय नकदी प्रवाह और व्यवसाय क्षमता पर आधारित होना चाहिए।

निष्कर्ष

- यद्यपि संयुक्त देयता समूह मॉडल ने भारत में वित्तीय समावेशन का उल्लेखनीय विस्तार किया है, इसकी भविष्य की वृद्धि क्षमता सीमित होती जा रही है।
- मेसो-फाइनेंस, सशक्त बचत प्रणाली और विविधीकृत वित्तीय सेवाओं की ओर संक्रमण एक अधिक लचीला एवं समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायक होगा।

स्रोत: BS

भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

समाचार में

- भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ, जिससे खाड़ी क्षेत्र में भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक स्थापित हुआ।

CEPA क्या है?

- CEPA पारंपरिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से आगे जाता है। जहाँ पारंपरिक FTA केवल वस्तुओं पर केंद्रित होते हैं, वहीं CEPA दो अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ता है, जिसमें वस्तुओं में वरीयता प्राप्त व्यापार, सेवाओं का उदारीकरण, निवेश संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति और सरकारी खरीद शामिल हैं।

भारत–ओमान CEPA की प्रमुख विशेषताएँ

- **भारतीय निर्यातों के लिए विशाल बाज़ार पहुँच**: भारत के 99.38% निर्यातों पर शुल्क-मुक्त पहुँच, जबकि MFN व्यवस्था के अंतर्गत केवल 15.33%।
    - **रणनीतिक साझेदारी**: ओमान भारत का खाड़ी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अपनी उन्नत बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से व्यापक GCC बाज़ार का रणनीतिक प्रवेश द्वार है।
    - **द्विपक्षीय व्यापार**: भारत और ओमान के बीच FY 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार $11.18 अरब तक पहुँच गया, जो FY 2024-25 के $10.61 अरब से अधिक है।
- **सेवाओं का सशक्त उदारीकरण**: ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्र खोले हैं, जो भारत के लिए किसी भी GCC देश द्वारा सबसे व्यापक प्रस्ताव है। प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)।
- **व्यापार सुविधा उपाय**: ओमान भारत के निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को स्वीकार करेगा। इससे परीक्षण में देरी कम होगी और निर्यातकों के लिए लेन-देन लागत घटेगी।

महत्व

- **ओमान का रणनीतिक स्थान**: अधिकांश खाड़ी देशों के विपरीत जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर निर्भर हैं, ओमान का अधिकांश तट सीधे अरब सागर और ओमान की खाड़ी पर स्थित है। इसका अर्थ है कि सलालाह और दुक़्म जैसे बंदरगाह होर्मुज़ यातायात बाधित होने पर भी सुलभ रहते हैं।
- **GCC और पूर्वी अफ्रीका का प्रवेश द्वार**: ओमान के सोहर, दुक्म और सलालाह में स्थित लॉजिस्टिक्स केंद्र भारतीय निर्यातकों को न केवल ओमान बल्कि व्यापक GCC और पूर्वी अफ्रीकी बाज़ारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं।
    - ओमान भारत का खाड़ी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अपनी उन्नत बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से व्यापक GCC बाज़ार का रणनीतिक प्रवेश द्वार है।
- **भारत की खाड़ी रणनीति**: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, ओमान के साथ व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता सुरक्षित करने वाला दूसरा देश बन गया है।
- **MSME और रोजगार**: संतुलित उदारीकरण दृष्टिकोण संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है, साथ ही MSME, श्रम-प्रधान उद्योगों और क्षेत्रीय स्तर पर निर्यात वृद्धि को समर्थन देता है।

भारत द्वारा निर्यात बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम

- **RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी)**: निर्यातकों को अंतर्निहित करों और शुल्कों की वापसी, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
- **निर्यात संवर्धन मिशन**: सस्ती व्यापार वित्त, प्रमाणन सहायता और बाज़ार पहुँच पहलों के माध्यम से निर्यातकों को समर्थन।
- **जिला स्तर पर निर्यात केंद्र**: जिला स्तर पर निर्यात-उन्मुख विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा।
- **विदेश व्यापार नीति (FTP), 2023**: 2030 तक माल और सेवाओं के निर्यात को USD 2 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य।

स्रोत: TH

क्लाउड कंप्यूटिंग के युग में डिजिटल संप्रभुता

संदर्भ

- नायरा एनर्जी के लिए अमेरिकी प्रतिबंध अनुपालन के कारण माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में व्यवधान की संभावना ने भारत में डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता को रेखांकित किया।

डिजिटल संप्रभुता क्या है?

- डिजिटल संप्रभुता का आशय किसी राष्ट्र की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपने डिजिटल अवसंरचना, डेटा, प्रौद्योगिकियों और साइबरस्पेस को अपने कानूनों एवं रणनीतिक हितों के अनुसार नियंत्रित कर सके।

- इसमें डेटा भंडारण, क्लाउड अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियाँ, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाएँ और महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं पर नियंत्रण शामिल है।

डिजिटल संप्रभुता के महत्व का कारण

- **डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता**: सरकारें, बैंक, अस्पताल, व्यवसाय और महत्वपूर्ण अवसंरचना तीव्रता से क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो रही हैं।
    - इन सेवाओं में व्यवधान आर्थिक गतिविधि, शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
- **भूराजनीतिक विखंडन**: प्रमुख शक्तियों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा वैश्विक डिजिटल परिदृश्य को पुनः आकार दे रही है।
    - प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण और प्रौद्योगिकी प्रतिबंध तीव्रता से भूराजनीतिक प्रभाव के उपकरण के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं।
- **डेटा का रणनीतिक महत्व**: डेटा एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक संसाधन के रूप में उभरा है और डेटा प्रवाह पर नियंत्रण आर्थिक प्रतिस्पर्धा, नवाचार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) मॉडल

- **आधार**: विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक-आधारित डिजिटल पहचान प्रणाली स्थापित की, जिससे सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक सुरक्षित अवं समावेशी पहुँच संभव हुई।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)**: डिजिटल भुगतान में क्रांति लाकर त्वरित, कम लागत और अंतःसंचालनीय वित्तीय लेन-देन को संभव बनाया, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
- **डिजीलॉकर और ई-साइन**: सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज़ भंडारण और विधिक रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण सेवाएँ प्रदान कर कागजरहित शासन को सक्षम बनाया।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)**: अंतःसंचालनीय स्वास्थ्य अभिलेखों और निर्बाध स्वास्थ्य सेवा वितरण के माध्यम से एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)**: एक खुला, अंतःसंचालनीय और प्लेटफॉर्म-तटस्थ डिजिटल बाज़ार को प्रोत्साहन देकर ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास।

भारत की डिजिटल यात्रा में अवसंरचना अंतराल

- **विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता**: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड द्वारा प्रदत्त क्लाउड सेवाओं पर संचालित होता है।
- **महत्वपूर्ण डेटा और सेवाएँ** विदेशी न्यायक्षेत्रों द्वारा शासित अवसंरचना पर निर्भर हैं।
- **विदेशी AI मॉडलों पर निर्भरता**: अधिकांश उन्नत AI प्रणालियाँ और बड़े भाषा मॉडल (LLMs) अमेरिका अवं चीन स्थित कंपनियों द्वारा विकसित किए गए हैं। भारत का उनके प्रशिक्षण डेटा, एल्गोरिद्म, सुरक्षा मानकों और शासन ढाँचों पर सीमित नियंत्रण है।
- **सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता**: सेमीकंडक्टर डिजिटल प्रौद्योगिकियों का आधार हैं और भारत अभी भी आयातित चिप्स अवं विदेशी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी निर्भर है।

डिजिटल निर्भरता से जुड़े जोखिम

- **रणनीतिक स्वायत्तता के लिए खतरा**: महत्वपूर्ण सेवाएँ भूराजनीतिक संकटों के दौरान असुरक्षित हो सकती हैं क्योंकि विदेशी सरकारें प्रतिबंध या नियामक उपायों के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकती हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ**: बाहरी अवसंरचना पर निर्भरता महत्वपूर्ण प्रणालियों को साइबर जोखिमों और आपूर्ति श्रृंखला कमजोरियों के प्रति उजागर कर सकती है।
- **आर्थिक कमजोरियाँ**: विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक निर्भरता आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण का कारण बन सकती है और घरेलू नवाचार एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को कम कर सकती है।
- **सीमित नीतिगत नियंत्रण**: विदेशी स्वामित्व वाली डिजिटल अवसंरचना अपने मूल देश के कानूनों के अधीन होती है और राष्ट्रीय नियामकों को आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्ण पर्यवेक्षण करने में कठिनाई हो सकती है।

डिजिटल संप्रभुता प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **उच्च अवसंरचना लागत**: घरेलू क्लाउड, AI और सेमीकंडक्टर क्षमताओं का निर्माण भारी निवेश की माँग करता है।

- **प्रौद्योगिकी अंतराल**: उन्नत प्रौद्योगिकियों में उच्च प्रवेश बाधाएँ और सीमित स्वदेशी विशेषज्ञता शामिल है।
- **संरक्षणवाद का जोखिम**: अत्यधिक प्रतिबंध प्रतिस्पर्धात्मकता और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को कम कर सकते हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता**: डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ जटिल अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करती हैं जिन्हें पूरी तरह स्थानीयकृत करना कठिन है।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक क्लाउड अवसंरचना का विकास**: भारत को मेघराज जैसी स्वदेशी क्लाउड पहलों का विस्तार करना चाहिए और घरेलू क्लाउड प्रदाताओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **डेटा शासन का सशक्तिकरण** : संवेदनशील और महत्वपूर्ण डेटा भारत के न्यायक्षेत्र के भीतर संग्रहीत और संसाधित किया जाना चाहिए।
- **स्वदेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहन** : AI अनुसंधान, कंप्यूटिंग अवसंरचना और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा मॉडलों में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बेहतर करना**: भारत को अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ DPI साझेदारियों का लाभ उठाना चाहिए।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

अहिल्याबाई होल्कर (1725–1795) के बारे में

- वह होल्कर वंश की प्रतिष्ठित रानी थीं जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मालवा राज्य पर शासन किया।
- उन्हें उनके प्रबुद्ध और जन-केंद्रित शासन के कारण "दार्शनिक रानी" के रूप में सम्मानित किया जाता है।
- उनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के चौंडी गाँव में हुआ था। उनका विवाह खंडेराव होल्कर से हुआ, जो मल्हारराव होल्कर के पुत्र थे। पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने 1767 में मालवा का प्रशासन संभाला।

प्रमुख योगदान

- उनका स्मरण न्याय के आदर्श, कल्याणोन्मुख शासन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किया जाता है।
- अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया।
- उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सती जैसी प्रथाओं का विरोध किया।
- उन्होंने जनजातीय समुदायों और निम्न जातियों के उत्थान के लिए भी कार्य किया।
- उनके शासनकाल में महेश्वर और इंदौर प्रमुख व्यापार केंद्र बने और प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी परंपरा फली-फूली।

स्रोत: PIB

पीएम स्वनिधि योजना के छह वर्ष पूर्ण

संदर्भ

- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना ने छह वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने सड़क विक्रेताओं को सस्ती, बिना संपार्श्विक ऋण, डिजिटल समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया है।

पीएम स्वनिधि योजना के बारे में

- पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 1 जून 2020 को COVID-19 महामारी से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने हेतु शुरू किया गया।
- **क्रियान्वयन एजेंसियाँ**: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग।
- **पात्रता मानदंड**: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले सड़क विक्रेता।

- **पीएम स्वनिधि योजना की प्रमुख विशेषताएँ:**
    - **कार्यशील पूंजी ऋण**: ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 के बिना संपार्श्विक ऋण तीन क्रमिक किश्तों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें ब्याज सब्सिडी एवं क्रेडिट गारंटी समर्थन शामिल है।
    - **UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड**: दूसरी किश्त का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वाले विक्रेताओं को ₹30,000 तक की सीमा वाले UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं।
    - **डिजिटल अपनापन**: सड़क विक्रेताओं को खुदरा और थोक डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
    - **स्वनिधि से समृद्धि (SSS)**: लाभार्थियों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार किया जाता है ताकि उन्हें आठ चयनित केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके तथा एक समग्र सामाजिक सुरक्षा जाल बनाया जा सके।

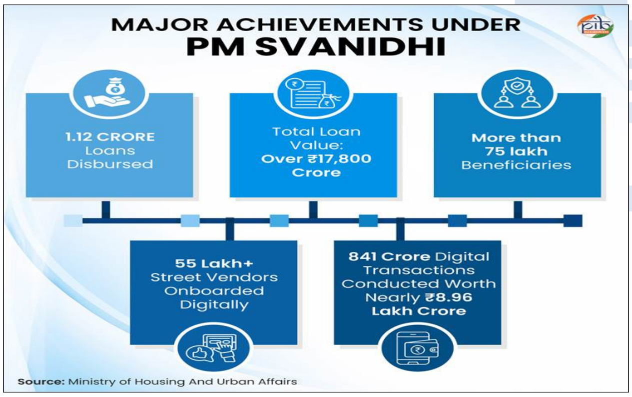

स्रोत: PIB

शांग्री-ला संवाद

समाचार में

- भारत ने आधिकारिक रूप से वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें आपूर्ति करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी पुष्टि सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला संवाद में हुई।
    - ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक संयुक्त उद्यम मिसाइल प्रणाली है जिसे भारत और रूस ने विकसित किया है।

परिचय

- इसे एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है और यह एशिया का प्रमुख रक्षा एवं सुरक्षा मंच है।
- इसकी स्थापना 2002 में हुई और यह प्रतिवर्ष सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में आयोजित होता है।
- इसका आयोजन लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ (IISS) द्वारा सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।
- संवाद में पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों (सीमाई विवाद, सैन्य सहयोग) और गैर-पारंपरिक चुनौतियों (आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- इसमें मुख्य भाषण, पूर्ण सत्र, विशिष्ट चर्चाएँ और द्विपक्षीय बैठकें शामिल होती हैं।
- भारत का रायसीना संवाद शांग्री-ला संवाद पर आधारित माना जाता है।

स्रोत: LM

बन्नी घासभूमि

संदर्भ

- गुजरात की बन्नी घासभूमि में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सौर परियोजना ने स्थानीय समुदायों, जैव विविधता एवं आर्द्रभूमियों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

बन्नी घासभूमि के बारे में

- कच्छ की बन्नी घासभूमि एशिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक घासभूमियों में से एक है और यह फकीरानी जाट जैसी पशुपालक समुदायों का समर्थन करती है।
- इस क्षेत्र में 70 से अधिक पौष्टिक घासों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और यहाँ ऊँट, भैंस, भेड़ एवं बकरियों का चरागाह होता है।
- समीप स्थित छारी ढांढ आर्द्रभूमि संरक्षण आरक्षित क्षेत्र एक रामसर स्थल है जो प्रवासी पक्षियों और स्थानीय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है।

सौर परियोजना को लेकर चिंताएँ

- प्रस्तावित परियोजना लगभग 4,500 एकड़ क्षेत्र में फैली है जो 16 गाँवों को कवर करती है और यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के निकट स्थित है।
- स्थानीय समुदायों को चरागाह भूमि, सांस्कृतिक स्थलों, कब्रिस्तानों और पारंपरिक आजीविका की हानि का भय है।
- संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि सौर अवसंरचना, प्रकाश प्रदूषण एवं मानवीय गतिविधियाँ पक्षियों के आवास और प्रवासी मार्गों को बाधित कर सकती हैं।
- सौर पैनल पक्षियों को भ्रमित कर सकते हैं जिससे टकराव का जोखिम बढ़ सकता है।
- चरागाह भूमि और वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित सुरक्षा उपायों के कमजोर क्रियान्वयन को लेकर भी चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

स्रोत: TH

■■■■

NEXT IAS